



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 22, 2013/आश्विन 30, 1935

No. 530]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2013/ASVINA 30, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2013

सं. 25/2013- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 698(अ).- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य या यूनाइटेड अरब अमीरात (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित, या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित किये जाने वाले विट्रीफाइड और पोर्सलिन टाइल्स (जिसे एतश्मिन पश्चात विषयगत माल से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 69 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में नामित प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्षों के तहत, अधिसूचना सं. 37/1/2001-डीजीएडी, दिनांक 4 फरवरी, 2003, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खण्ड I में दिनांक 4 फरवरी, 2003 को प्रकाशित किया गया था, में विषयगत देश से होने वाले विट्रीफाइड और पोर्सलिन टाइल्स के सभी आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की थी जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति न हो ;

और जहां कि नामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 73/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मई, 2003, जिसे सा.का.नि. 376 (अ), दिनांक 1 मई, 2003 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित किये जाने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 69 के अंतर्गत आने वाले विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल के प्रतिपाटन शुल्क की सनसैट समीक्षा के मामले में, नामित प्राधिकारी ने अपने निष्कर्षों अधिसूचना सं. 15/17/2006-डीजीएडी, जोकि भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खण्ड I में दिनांक 23 अप्रैल, 2008 को प्रकाशित किया गया था, जिसे अधिसूचना सं. 15/17/2006-डीजीएडी, जोकि भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खण्ड I में दिनांक 21 मई, 2008 में प्रकाशित के तहत संशोधित किया गया था में चीन (जन.गण.) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल के सभी आया पर प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने की सिफारिश की थी जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति न हो;

और जहां कि नामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 82/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 27 जून, 2008, जिसे सा.का.नि. 485 (अ), दिनांक 27 जून, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत चीन (जन.गण.) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 6907 या 6908 या 6914 के अंतर्गत आने वाले विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि मैसर्स फोशन क्विआंगबिआओ सिरैमिक कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.(उत्पादक) और मैसर्स शीनवे कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग ने अपने द्वारा किये गये विषयगत माल के आयात की सीमा शुल्क टैरिफ (प्रतिपाटित वस्तुओं के अभिज्ञान, आकलन और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण), नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 22 की दृष्टि से समीक्षा करने का अनुरोध किया था और नामित प्राधिकारी ने अपने नये शिपर रिव्यू अधिसूचना सं. 15/20/2011-डीजीएडी, दिनांक 19 अप्रैल, 2012 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खण्ड I में दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को प्रकाशित किया गया था में उपर्युक्त पार्टी द्वारा किये गये विषयगत माल के सभी आयातों का तब तक के लिए अनंतिम आकलन किये जाने की सिफारिश की थी जब तक कि इसके द्वारा समीक्षा का काम पूरा नहीं हो जाता है;

और जहां कि उक्त नियमावली के नियम 22 के उप-नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने नामित प्राधिकारी के सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त

मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/2012-सीमा शुल्क(एडीडी) दिनांक 10 जुलाई, 2012, जिसे सा.का.नि. 551 (अ), दिनांक 10 जुलाई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत विचार करने के पश्चात आदेश दिया है कि नातिम प्राधिकारी के द्वारा उक्त समीक्षा के निष्कर्ष विचाराधीन रहने के कारण विषयगत माल, जब इनका निर्यात मैसर्स फोशन क्विआंगबिआओ सिरैमिक कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.(उत्पादक) और मैसर्स शीनवे कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग (निर्यातक) द्वारा किया गया हो और भारत में उनका आयात किया गया हो, तब तक अनंतिम समीक्षा के अधीन रहेंगे जब तक कि इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है;

और जहां कि नामित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खण्ड I में दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/20/2011-डीजीएडी के अंतर्गत शुरू किए गए न्यू शिपर रिव्यू मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खण्ड I में प्रकाशित दिनांक 24 जुलाई, 2013 की अधिसूचना सं. 15/20/2011-डीजीएडी में अपने अंतिम निष्कर्ष के अंतर्गत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मैसर्स फोशन क्विआंगबिआओ सिरैमिक कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.(उत्पादक) और मैसर्स शीनवे कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग द्वारा भारत को विट्रीफाइड/पोर्सिलिन टाइल्स किए गए निर्यातों के बारे में कोई भी व्यक्तिगत पाटन मार्जिन औचित्यपूर्ण नहीं है और सिफारिश की कि मैसर्स फोशन क्विआंगबिआओ सिरैमिक कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.(उत्पादक) और मैसर्स शीनवे कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग (निर्यातक) चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 69 के अंतर्गत आने वाले विट्रीफाइड पोर्सिलीन टाइल्स के निर्यातों के बारे में दिनांक 27 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या 82/2008-सीमा शुल्क के तहत यथा-लागू भारतीय रूपए में 155 रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क की अवशिष्ट दर का भुगतान करेंगे।

अब उपर्युक्त नियमावली के नियम 18, 20, 22 और 23 के साथ पठित उपर्युक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते केन्द्र सरकार एतद्वारा यह आदेश देती है कि मैसर्स फोशन क्विआंगबिआओ सिरैमिक कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.(उत्पादक) और मैसर्स शीनवे कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग (निर्यातक) द्वारा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुएं जो कि सा.का.नि.सं. 551(अ) भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) दिनांक 10 जुलाई, 2012 में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 जुलाई, 2012 के अनुक्रम में अनंतिम मूल्यांकन के अध्याधीन, 155 रूपये प्रति वर्गमीटर प्रतिपाटन शुल्क की अदायगी पर अंतिम मूल्यांकन के अध्याधीन होगा।

[फा. सं. 354/214/2001-टीआरयू (भाग-4)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department Of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2013

**No. 25/2013-Customs (ADD)**

**G.S.R. 698 (E).**— Whereas, in the matter of import of vitrified and porcelain tiles (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapter 69 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and originating in, or exported from the People's Republic of China (China PR) or United Arab Emirates (UAE) (hereinafter referred to as the subject countries), the designated authority, *vide* its final findings in notification No. 37/1/2001-DGAD dated the 4th February, 2003 in the original anti-dumping case published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 4th February, 2003 had recommended imposition of anti-dumping duty on all imports of vitrified and porcelain tiles from subject countries in order to remove the injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on subject goods falling under Chapter 69 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from the subject countries and imported into India *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 73/2003-Customs, dated the 1st May, 2003, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, G.S.R. 376(E) dated the 1st May, 2003;

And whereas, in the matter of sunset review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries, the designated authority *vide* its findings, No. 15/17/2006-DGAD, dated the 21st April, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd April, 2008 subsequently amended *vide* Notification No. 15/17/2006-DGAD, dated the 21st May, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had recommended continued imposition of the anti-dumping duty on the subject goods originating in, or exported from China PR in order to remove injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on subject goods falling under heading 6907 or 6908 or 6914 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR and imported into India *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 82/2008-Customs, dated the 27th June, 2008 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, G.S.R. 485(E) dated the 27th June, 2008;

And whereas, M/s Foshan Qiangbiao Ceramics Co. Ltd, China PR (producer) through M/s Sheenway Corporation Ltd., Hong Kong (exporter) had requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules) in respect of exports of the subject goods made by them, and the designated authority, *vide* new shipper review notification No. 15/20/2011-DGAD dated the 19th April, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19th April, 2012, had recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the above stated party when imported into India, till the completion of the said review;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 22 of the said rules, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), notification No. 35/2012-Customs (ADD), dated the 10th July, 2012, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 551 (E), dated the 10th July, 2012 had ordered that pending the outcome of the said review by the designated authority, the subject goods, when exported by M/s Foshan Qiangbiao Ceramics Co. Ltd, China PR (producer) through M/s Sheenway Corporation Ltd., Hong Kong (exporter) and imported into India, shall be subjected to provisional assessment till the review is completed;

And whereas, the designated authority in the matter of new shipper review initiated *vide* notification No. 15/20/2011-DGAD dated the 19th April, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19th April, 2012, *vide* its final findings in notification No. 15/20/2011-DGAD dated the 24th July, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th July, 2013 has concluded that no individual dumping margin is justified in respect of exports of the subject goods made to India by M/s Foshan Qiangbiao Ceramic Co. Ltd, Foshan, China PR (Producer) through M/s Sheenway Corporation Ltd., Hong Kong and has accordingly recommended that M/s Foshan Qiangbiao Co. Ltd, China PR (Producer) and M/s Sheenway Corporation Ltd., Hong Kong (Exporter) shall be liable for payment of the residual rate of duty in Indian rupees at the rate of ₹155 per square meter as applicable *vide* notification No 82/2008-Customs dated the 27th June, 2008 in respect of exports of vitrified and porcelain tiles falling under Chapter 69 of the Customs Tariff Act, 1975 originated in or exported from China PR;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18, 20, 22 and 23 of the said rules, the Central Government, hereby orders that all imports of the subject goods by M/s Foshan Qiangbiao Ceramics Co. Ltd, China PR (producer) through M/s Sheenway Corporation Ltd., Hong Kong (exporter) which have been subjected to provisional assessment pursuant to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 35/2012-Customs (ADD), dated the 10th July, 2012, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 551(E), dated the 10th July, 2012 shall be subjected to final assessment on the payment of anti-dumping duty of ₹155 per square meter.

[F. No. 354/214/2001-TRU (Pt. 4)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.